भाजपा सरकारों की उपलब्धियां

भारतीय जनता पार्टी
प्रशिक्षण महाभियान 2015
11, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

भाजपा सरकारों की उपलब्धियां

भारतीय जनता पार्टी
çf'k{k.k egkfHk;ku 2015
11] v'kkd jkM] ubZ fnYyh& 110001

आमुख

भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का सत्ता में आना भारतीय राजनीति के इतिहास में परिवर्तन का एक निर्णायक 'माइल स्टोन' है। जब हमने 'स्वराज्य' की यात्रा को 'सुराज्य' के पथ पर अग्रसर किया। केन्द्र और राज्यों में इन सरकारों ने अद्‌भुत कार्य किए, जो अपने आप में रेखांकनीय हैं।

2014 में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार प्रस्थापित हुयी है। शपथ ग्रहण समारोह के समय ही एक सुडोल दक्षिण एशिया एवं स्वदेशनीति का दिग्दर्शन हुआ। विगत वर्ष में इतनी सकारात्मक पहलें इस सरकार ने की है, जिसका असर समाज पर दिखने लगा है। विश्व में भारतीय जन गर्वोन्नत हैं।

पं. दीनदयाल प्रशिक्षण महाभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हम कार्यकर्ता अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सम्पन्न हो रही इन सकारात्मक उपलब्धियों को जाने और हृदयंगम करें, यह अपेक्षित है। अतः यह संक्षिप्त पुस्तिका आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि समुचित जानकारियों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता अब 'लोकमत परिष्कार' के कार्य में जुटेंगे।

पी. मुरलीधर राव

¼jk"Vªh; egklfpo½

iHkkjh

ifk'k{k.k egkfHk;ku

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर...
भाजपा सरकार की उपलब्धियां

श्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में जिस आमूल-चूल परिवर्तन के कारण भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, उसका पूरा प्रभाव अभी दिखना बाकी है। किंतु यह बात सबकी समझ में आ गई है कि मई 2014 के चुनावों में भाजपा को जैसी भारी जीत मिली, वैसी जीत का कोई उदाहरण अतीत में नहीं मिलता और यही कारण है कि विदेशी मोर्चे पर भारतीय प्रधानमंत्री के काम को हर ओर से सराहना मिल रही है। भाजपा की जीत इतनी विराट और भव्य थी कि लंदन से प्रकाशित होने वाले द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत ने आखिरकार ब्रिटिश विरासत से पल्ला झाड़ लिया है। उस टिप्पणी में विस्तार से न जाएं तब भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाजपा की सफलता में दुनिया ने ऐसे भारत की झलक देखी गई, जो अतीत की छाया और बेड़ियों से मुक्त हो चुका है। एक तरह से यह भारत की सांस्कृतिक मजबूती और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं की स्पष्ट घोषणा ही थी, जिसने चुनावों का नतीजा तय किया। कुछ लोगों ने इस बात को माना, उनमें से भी कुछ ने इस पर प्रसन्नता जताई, लेकिन भाजपा में हमने – जनमत के संदेश को पूरी तरह आत्मसात किया है और हमारे कार्य बोल रहे हैं।

इसलिए भारत के पुनर्निर्माण में, मातृभूमि और इस धरती के प्रत्येक निवासी के लिए परम वैभव के सपने को फिर से परिभाषित करने, फिर से समझाने और ईंट-ईंट जोड़कर तैयार करने के विराट कार्य को शून्य से आरंभ करने में हाल के महीने अद्भुत एवं आकर्षक गाथा सरीखे रहे। स्वच्छ भारत से लेकर सभी के लिए आवास तक, प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ पेयजल से लेकर बिजली तक, हमारी माताओं एवं बहनों के लिए गरिमा तथा सम्मान से लेकर कन्या भ्रूण हत्या पर विराम लगाने तक, प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर सभी के लिए कौशलपूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा तक, वित्तीय समावेश से लेकर प्रत्येक परिवार को विपन्नता से बचाने तक – सबका विकास सब के साथ – वह विश्वास भरा वह कथन है, जो संकल्प से भरे हमारे मानस पर दर्ज हो गया है। पिछले पंद्रह महीने में भाजपा सरकार के कार्य स्वयं बताते हैं कि हमारी योजनाओं में राष्ट्र निर्माण की कितनी छाप है। इसमें सबसे उत्कृष्ट पक्ष यह है कि सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों में स्वयं सत्यापन आरंभ कर, 400 से अधिक पुराने एवं अपमानजनक कानून समाप्त कर, प्रवासी भारतीयों की चिंता कर, विश्व में कहीं भी मौजूद प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्रयास कर, राजनय को किसी भी स्थान पर भारतीयों की सहायता का प्रभावी माध्यम बनाकर, अशांत क्षेत्रों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर, भारत की धरती पर युद्ध के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाकर, बिचौलियों को समाप्त कर, निविदा की प्रक्रिया और नीलामी को पारदर्शी बनाकर, डिजिटल इंडिया आरंभ कर और सभी प्रयासों के केंद्र में नागरिकों को लाकर सरकार ने किस तरह देश के नागरिकों का विश्वास जीतने का प्रयास किया है। नया तरीका यह है कि अपराधियों को सजा देते और अपराध समाप्त करते हुए भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास भी किया जाए, काले धन का पता लगाया जाए, लेकिन इसकी जड़ को भी समाप्त किया जाए, कुशल भारत की मदद से भारत निर्माण किया जाए। दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन दिखता है।

जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कहा,

''सरकार वह होती है, जो गरीबों के बारे में सोचती है, गरीबों को

सुनती है और गरीबों के लिए ही होती है। इसलिए नई सरकार गरीबों के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए और माताओं तथा बहनों के लिए समर्पित है, जो सम्मान एवं गरिमा चाहते हैं। ग्रामीण, किसान, आदिवासी, दलित और वंचित, यह सरकार उन सभी के लिए है, उनकी आकांक्षाकों के लिए है और यह हमारा दायित्व है।'' (श्री नरेंद्र मोदी, 20 मई 2014, संसद का केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली)

राजनीति के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर ही अलग है क्योंकि हमारे लिए सत्ता लक्ष्य नहीं है बल्कि जनता के कल्याण एवं मातृभूमि के गौरव का साधन मात्र है। यही कारण है कि केंद्र और राज्यों में जब भी भाजपा सत्ता में आई, उसने ऐसी छाप छोड़ी, जिसका दावा कोई अन्य पार्टी कर ही नहीं सकती। आज भाजपा केंद्र में सत्ता में है और स्वयं अथवा सहयोगी दलों के साथ दस राज्यों में भी सत्ता में है। तीन दशकों में यह पहला अवसर है कि केंद्र में एक ही पार्टी को बहुमत मिला है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद शीघ्र ही स्वयं को भारत के पुनर्निर्माण, गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के अभियान में लगा लिया।

सिद्धांत

प्रशासन का हमारा मौलिक सिद्धांत है ''सबका साथ, सबका विकास''। राज्यों और केंद्र में भाजपा सरकारों ने अंत्योदय – जन भागीदारी के माध्यम से सबसे दरिद्र लोगों की सेवा करने – को अपना सिद्धांत बनाया है, जो लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला समग्र विकास का मॉडल है। इसमें टीम इंडिया के विचार अर्थात् सहयोगपरक एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को पूरी तरह काम करने की छूट दे दी जाती है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति केंद्र के भेदभाव के दिन बीत गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योजनागत धन एवं खनिज उत्खनन पर रॉयल्टी के मामले में राज्यों के लिए आवंटन बढ़ा दिया है।

प्रशासन एवं राजनीति

श्री मोदी के करिश्माई आकर्षण के कारण चुनावी अभियान में एक बार फिर बड़ी रैलियों का दौर आ गया। भारत को आधुनिक महाशक्ति बनाना ही उनका विचार था। ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के

संदेश ने अवसरों की तलाश कर रहे उम्मीदों भरे युवाओं से एकदम नाता जोड़ लिया। इस संदेश से पहले विपक्षी धड़े ने सांप्रदायिक और जातिवाद पर दांव लगाया, जो चित हो गया।

वंशवादी राजनीति के प्रति श्री नरेंद्र मोदी की वितृष्णा भी इसी से जुड़ी है। लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद का अखाड़ा हैं। मोदी के तूफान में झटका खाने से पहले कई पीढ़ियों से वे सुधरने से इनकार कर रही थीं। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता ने एक ही परिवार का आधिपत्य बनाए रखने की ओछी मानसिकता का लाभ उठाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खारिज भले न किया हो, लेकिन सबके सामने तो ला ही दिया। इसका दूरगामी प्रभाव यह है कि राजनीतिक अब बदल सकती है और सुशिक्षित एवं सेवा भाव वाले युवा इसे कैरियर के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। श्री मोदी ने इस वर्ग को बहुत आकर्षित किया।

उन्होंने आम आदमी और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर उनके लिए राजनीति की बिसात तैयार कर दी। इससे हमारे लोकतंत्र का अभूतपूर्व लोकतंत्रीकरण हुआ।

समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा श्री नरेंद्र मोदी के सबसे समर्पित समर्थक कौन थे? यह अद्भुत बात है कि चर्चा करने वालों को वह बहुत पसंद है। बाद में अक्सर वही उनकी चर्चा का विषय हुआ करते थे। एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को राजनीति से जोड़ दिया कि हमारी व्यवस्था को बदलने की संभावना पैदा हो गई। श्री मोदी मध्य वर्ग के ''कुछ नहीं बदल सकता, भारत में कुछ नहीं होगा'' वाले राग के उत्तर के रूप में आए। राजनीति में लोगों की रुचि जग गई, उम्मीद जग गई कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रगति हो सकती है। ''सब चोर हैं'' का राग खत्म हो गया है और राजनीतिक वर्ग की विश्वसनीयता बहाल हो गई है। यही कारण है कि जीवन में कभी वोट नहीं डालने का दावा करने वाले भी श्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड को अपनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। अच्छे दिन आने वाले हैं।

भाजपा ने अपना घोषणापत्र जनता की इस सामूहिक आशा से ही तैयार किया और सरकार में भाजपा इसे अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार पारदर्शिता एवं खुलेपन वाली

जवाबदेही के प्रति संकल्पबद्ध है। न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन हमारा ध्येय वाक्य है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार ने राजनीतिक एवं अफसरशाही व्यवस्था के विवेकाधिकारों को कम से कम करते हुए नीति से चलने वाले प्रशासन का सिद्धांत गढ़ा है। इससे प्रशासन अधिक जवाबदेह होगा।

अन्नदाता सुखी भव : किसानों का कल्याण

भाजपा के लिए कृषि आर्थिक विकास का प्रमुख क्षेत्र है। किसानों का कल्याण, अधिकतम कृषि उत्पादकता और किसान को लाभकारी आय सुनिश्चित करना इसके संकल्प का केंद्र बिंदु रहा है। सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही पार्टी की सरकार ने किसानों के कष्ट दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – 'हर खेत को पानी' नहर, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर से सिंचाई तथा वाटरशेड के विकास के लिए 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' को बड़े स्तर पर आरंभ किया गया है और पिछले दो बजटों में इनके लिए धन आवंटित किया गया है। पिछले चौदह महीनों में 1 लाख से अधिक सौर पंप मंजूर किए गए हैं तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के इरादे से आरंभ की गई सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के लिए व्यवस्था की गई है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और यूरिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नीम की परत वाली यूरिया प्रस्तुत की गई। घरेलू उत्पादन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नई यूरिया नीति की घोषणा की गई, जिसमें गोरखपुर, बरौनी तथा तलचर में उर्वरक संयंत्र फिर आरंभ करने की योजना है ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। किसानों की सहायता के लिए समर्पित किसान टीवी चैनल का आरंभ भी इसी दिशा में एक अन्य प्रमुख कदम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मवेशियों की देसी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने वाला एक अन्य अभियान है। किसानों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए भारत ने डब्ल्यूटीओ वैश्विक वार्ता में कड़ा रुख अपनाया, जो भाजपा सरकार के निर्णायक नेतृत्व का ही परिणाम था।

इसके साथ ही कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि रियायती दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कृषि में मोबाइल प्रशासन से लाभ मिला है और सुझाव एवं सूचना के रूप में लगभग 1 करोड़

किसानों को 550 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए हैं। केंद्र सरकार किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने हेतु राज्यों के साथ सक्रियता से काम कर रही है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) आरंभ की गई और गन्ना किसानों को सशक्त बनाने के लिए एथेनॉल मिश्रण में 250 प्रतिशत वृद्धि तथा आयात शुल्क में वृद्धि समेत विभिन्न कदमों की घोषणा की गई है। ये कदम कृषि को लाभकारी उपक्रम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भूमि विधेयक में संशोधन 13 कानूनों के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए अधिक मुआवजे के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने और सिंचाई, सड़क एवं सस्ते घर जैसा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करने एवं रोजगार सृजन करने तथा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली प्रमुख पहल हैं। सरकार ने फसल को क्षति होने पर मुआवजे में 50 प्रतिशत वृद्धि की है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए अर्हता भी 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत क्षति कर दी गई है। खरीद के लिए अनाज की गुणवत्ता के नियमों में ढील देने से किसानों को बहुत लाभ होगा। फसल हानि से प्रभावित किसानों के ऋण की शर्तें आसान करने का निर्णय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार का विचार किसानों की संपन्नता सुनिश्चित करना तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वालों को तुरंत सहायता पहुंचाना है।

भूमि सुधार का समर्थन

सभी भाजपा शासित राज्यों में किसानों ने अपेक्षाकृत सबसे कम आत्महत्या कीं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में है, कृषि का परिदृश्य गैर भाजपा शासित राज्यों से अलग कहानी कहता है। राहुल गांधी की पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का विकास दो प्रतिशत पर अटका रहा, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश एक दशक से भी अधिक समय से दहाई अंकों में कृषि विकास के साथ शीर्ष पर रहे हैं और पूरे देश का पेट भरते रहे हैं। सफलता की एक अन्य कहानी पंजाब है, जहां भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन में हैं।

इन सभी में गुजरात सबसे शानदार उदाहरण है क्योंकि इसे कभी

कृषि प्रधान राज्य नहीं कहा जाता था। गुजरात में कृषि की सफलता ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को इतना उत्साहित कर दिया कि उन्होंने आईआईएम, अहमदाबाद से पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए इसका अध्ययन करने को कहा। श्री मोदी ने गुजरात में कृषि की दहाई अंकों की विकास दर कैसे हासिल की? जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो राज्य लगातार सूखे से जूझ रहा था, पानी तथा रोजी–रोटी के लिए लोग अपने मवेशी लेकर दूसरे हिस्सों में चले जाते थे और राज्य की औसत कृषि विकास दर दो प्रतिशत से कम थी। गुजरात की सफलता को अन्य भाजपा शासित राज्यों ने भी अपनाया। आईआईएम अहमदाबाद से डॉ. रवींद्र ढोलकिया और उनकी टीम ने गुजरात के कृषि विकास पर बहुत अच्छी तरह से एक पुस्तक लिखी है, जिसे मैकमिलन ने प्रकाशित किया है।

गुजरात के किसान भारत में सर्वाधिक प्रसन्न और धनी हैं।

भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि में बड़ी सफलता

गुजरात औद्योगिक विकास की भी कहानी प्रस्तुत करता है। टाटा ने बंगाल क्यों छोड़ा और अपनी छोटी कार की परियोजना लेकर गुजरात क्यों गई? वाहन उद्योग हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को क्यों छोड़ रहा है और गुजरात में साणंद को भारत का डेट्रॉयट क्यों बना रहा है? बुनियादी ढांचे, श्रम की उत्पादकता और निवेश के माहौल के कारण श्री मोदी ने भारत में निवेश का माहौल सुधार दिया है। अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। दि इकनॉमिस्ट मानती है कि भारत को तेजी से बढ़ने और ''विश्व की सबसे गतिमान विशाल अर्थव्यवस्था'' बनकर उभरने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया है। विश्व बैंक और मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों ने श्री मोदी के भारत की साख बेहतर की है और उसे दुनिया भर में विकास में गिरावट के बीच आशा की किरण बताया है तथा भारत के इतिहास में पहली बार दहाई अंकों में वृद्धि का अवसर दस्तक दे रहा है।

समाजवादी मॉडल में भूमि ही उत्पादन श्रृंखला का मूल तत्व होती है। हारूद दोमार जैसे पूंजीवादी अर्थशास्त्री मानते हैं कि वृद्धि एक ही सामग्री 'पूंजी' का परिणाम होती है। भाजपा के आर्थिक

दृष्टिकोण 'एकात्म मानववाद' में मनुष्य केंद्र में होता है और उसकी सर्वाधिक प्रसन्नता ही अंतिम लक्ष्य होती है। यदि गांवों का जीवन बेहतर नहीं होता तो मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकता। श्री मोदी ने गुजरात को बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बेहतर सिंचाई, सूचना का बेहतर संचार और बेहतर शिक्षा तथा मार्केटिंग दिए हैं और पूरे देश के लिए भी वह यही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

निवेश, औद्योगीकरण के बगैर ये सुविधाएं ग्रामीण भारत तक नहीं पहुंच सकतीं। भारतीय किसान बेहतर जीवन स्थिति चाहता है। वह भारतीय मॉनसून की विफलता के दुष्चक्र का शिकार नहीं हो सकता। वामपंथी राजनेता और कांग्रेस में उनके वैचारिक अनुगामियों ने साठ वर्ष तक घड़ियाली आंसू बहाते हुए किसानों के कष्टों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, लेकिन उन्हें दूर करने का रास्ता नहीं तलाशा। संप्रग के अपने ही शब्दों में पर्यावरण संबंधी मंजूरी के कारण 30 लाख करोड़ रुपये फंस गए, जिसके लिए जयराम रमेश और जयंती नटराजन जिम्मेदार हैं। मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम दिनों में 25 अरब डॉलर की पूंजी भारत से बाहर चली गई।

पहली बार भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर समाधान का प्रयास किया है। और उसने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। उत्तर भारत के कर्ज देने वाले, गांवों के साहूकार, शून्य आर्थिक सफलता वाले चालाक राजनेता अपने निहित स्वार्थ के कारण सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे लोगों के साथ खड़े हो गए हैं, जिन्होंने कभी खेतों का जीवन ही नहीं देखा। यह ट्रैक्टरों, कृषि के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, भूमि सुधार और जमींदारी की समाप्ति के विरुद्ध पुराने संघर्षों जैसा है। भारतीय किसान के विरुद्ध इस षड्यंत्र का खुलासा करना ही होगा। कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। वह अपनी भूमि से बंधा है, उसका भाग्य फसल की सफलता या असफलता से तय होता है। उसे अपनी जमीन को आधुनिक बनने, मार्केटिंग करने और उससे धन कमाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। भूमि विधेयक यही कहता है। कांग्रेस की योजना में किसान सदैव सरकारी संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का मोहताज रहेगा। आदिवासी सदैव जंगलों में रहते हैं। क्या यही सशक्तिकरण है, बेड़ियों से मुक्ति है? क्या यही कांग्रेस का विकास मॉडल है?

आर्थिक वृद्धि ही विकास का प्रतीक है। भारतीय किसानों के लिए नए रास्ते और अवसर तलाशने की आवश्यकता है। किसान नेता विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की सभा में कोई किसान नेता नहीं था।

भूमि विधेयक कृषि को उद्योग के साथ जोड़ने का कदम है। यह आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा। भूमि अधिक कीमती हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वृद्धि तेज हो जाएगी। भूमि विधेयक किसानों को उद्यमी बनाने और अब तक भुला गए रोजगार सृजन तथा आय वितरण की संभावना बढ़ाने की दिशा में भी एक कदम है।

दुनिया के सभी विकसित देशों ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। देंग शियाओपिंग के शासनकाल में चीन के उप प्रधानमंत्री रह चुके ली लानचिंग अपनी पुस्तक ब्रेकिंग थ्रू में बताते हैं कि किस प्रकार कृषि सुधारों ने चीन को विश्व अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थान दिलाया। भारत को चीन के अनुभव से काफी कुछ सीखना है। समस्या को हर कोई जानता है। लेकिन केवल मोदी ने ही समाधान का प्रयास किया है।

सर्वे भवंतु सुखिनः – वंचितों को मुख्यधारा में लाना

श्रमेव जयते – श्रमिकों का सम्मान सुनिश्चित करना

भाजपा सामाजिक समरसता के प्रति संकल्पबद्ध है। उसकी सभी योजनाएं देश में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बहाल करने और सभी के लिए गरिमामयी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए है। पार्टी ने राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करने और उनकी स्मृति का सम्मान करने का भी संकल्प लिया है। इसी लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक बनाने के लिए दिल्ली तथा मुंबई में भूमि आवंटित की गई तथा दिल्ली में डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी गई। दलित उद्यमियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराने के लिए नया वेंचर कैपिटल फंड एवं ऋण विकास गारंटी योजना हमारे समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त करने का एक और प्रयास है। इसी प्रकार आदिवासी समुदायों के विकास के लिए वन बंधु योजना तथा आदिवासी बच्चों में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए विशाल

कार्यक्रम, आदिवासी भारत की सांस्कृतिक विरासत दर्शाने के लिए पहला राष्ट्रीय आदिवाी उत्सव, विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए भारत को सुगम बनाने हेतु सुगग्य भारत अभियान, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास – उस्ताद योजना, 86 लाख अल्पसंख्यक बच्चों (46 प्रतिशत लड़कियों) के लिए छात्रवृत्ति की योजना केंद्र में भाजपा सरकार के पहले वर्ष में आरंभ किए गए कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं।

अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए

मदरसे के छात्रों के कौशल विकास के लिए 'अर्न एंड लर्न' रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम है। वक्फ संपत्ति का प्रयोग सामुदायिक उद्देश्यों में किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन की गारंटी दी गई है। भविष्य निधि खाते को पोर्टेबल, झंझट मुक्त और सुगम बनाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले ही बेहद सफल हो चुका है। ईपीएफ में बिना दावे के पड़े 27,000 करोड़ रुपये लौटाने का अभियान, चौबीस घंटों की हेल्पडेस्क, 9 लाख से अधिक इकाईयों को श्रमिक पहचान क्रमांक (लिन), 8 श्रम कानूनों के अनुपालन को ऑनलाइन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल कम समय में ही बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। इससे श्रमिकों को ईपीएफ और एनपीएस पेंशन योजनाओं में से कोई एक और ईएसआई तथा किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना में से कोई एक चुनने का विकल्प मिल गया है।

नारी शक्ति, देश की तरक्की – हमारी बेटियां, हमारा गौरव

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या एवं नवजात कन्या हत्या जैसी शर्मनाक घटनाएं समाप्त करने के लिए बड़ी योजना आरंभ की है। देश में पहले कभी इतनी विशाल और सामाजिक संदेश देने वाली योजना नहीं चलाई गई थी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बच्चे एवं मां का स्वास्थ्य बेहतर करने पर विशेष ध्यान के साथ हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है।

10 वर्ष के सरकारी बॉण्डों पर प्रतिफल से 0.75 प्रतिशत अधिक ब्याज (इस वर्ष 9.2 प्रतिशत) की गारंटी और कर में छूट के साथ 10 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के लिए विशेष जमा खाते ने डाकघरों में 43 लाख खाते खुलवाए हैं, जिनमें कुल 562 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इससे पता चलता है कि योजना में कितनी रुचि ली गई है। इसके साथ दिल्ली तथा अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक समानता की दिशा में मील का बड़ा पत्थर है।

पुलिस नेटवर्क बढ़ाने तथा सुरक्षा के अन्य उपाय करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ऐप हिम्मत आरंभ की गई है। खोए बच्चों की सूचना देने और उन्हें तलाशने के विशेष अभियान के अंतर्गत 3000 बच्चे तलाशे गए हैं और परिवारों तक पहुंचाए गए हैं।

जन धन से जन सुरक्षा – आर्थिक समावेश एवं सुरक्षा

दुनिया भर में कंपनी प्रमुख इस बात पर एकमत हैं कि भारत विश्व की नई आर्थिक संरचना के केंद्र में प्रवेश कर रहा है। यह सक्रियता भरी जगह है, उम्मीदों की धरती है।

बेचैनी, मोहभंग, लुढ़की वृद्धि दर और पूंजी पलायन वाली धरती को निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान, कारोबार करने के लिए आसान स्थान बनाने में कुछ ही महीने लगे। मोदी ने भारत का रुख ही बदल दिया। 2014 और 2015 की आर्थिक समीक्षाओं की तुलना से पता चलता है कि भारत किस प्रकार बदला है। नई आर्थिक समीक्षा भारत के इतिहास में पहली बार अगले वर्ष ही दहाई अंकों में और इस वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की बात करती है। एक वर्ष पहले भारत 4 प्रतिशत वृद्धि दर की ओर लुढ़क रहा था।

पिछले वर्ष मई में राजग के सत्ता में आने के बाद अपने पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली व्यावहारिकता एवं राजनीति के मिश्रण को संभालने में सफल रहे हैं, जिस पर मोदी की स्पष्ट मुहर है। कल्पनाशील एवं सधा हुआ संतुलन ही नए बजट की पहचान है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''मेरे प्रस्ताव वृद्धि तेज करने, निवेश बढ़ाने और विकास के लाभ सामान्य पुरुष, महिला, युवा और बच्चे तक

पहुंचाने का खाका तैयार करते हैं।''

बजट में 8.5 प्रतिशत वृद्धि, 3.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे, 14 प्रतिशत सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की सुगम आवाजाही से भारत को एकल आर्थिक क्षेत्र बनाने के उद्देश्य, अगले चार वर्ष में बेहतर अनुपालन के साथ कॉर्पोरेट कर को 25 प्रतिशत तक पहुंचाने, वेल्थ टैक्स हटाने और 1 करोड़ रुपये से अधिक आय पर 2 प्रतिशत अधिभार लगाने की बात कही गई है। किसी संपादकीय में कहा गया कि श्री जेटली ने वह कर दिखाया, जिसमें उनसे पहले के वित्त मंत्री प्रयास करके भी असफल रहे थे। एक अन्य संपादकीय में लिखा था कि धीरे-धीरे किंतु निश्चित रूप से यह बड़ा नहीं लेकिन ताकतवर है। स्पष्ट रूप से भारत वैश्विक राह पर है और वैश्विक विकास में मील का पत्थर प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है। यदि बजट के अनुमान सही होते हैं तो भारत दुनिया में सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करेगा। सभी के लिए घर का सपना पूरा करने के लिए इसने आने वाले वर्षों में 5 करोड़ मकान बनाने का वायदा किया है। काले धन पर सख्ती करने और विदेश में नकदी और संपत्ति रखने वालों को उसका खुलासा करने अथवा परिणाम भुगतने के लिए कहने वाला सख्त कानून बनाने की इसकी योजना है।

बजट में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए कई अनूठे प्रस्ताव हैं। यह साहसिक है, समावेशी है और इसने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों तथा छात्रों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा है।

कच्चे तेल में गिरावट से देश के आयात व्यय में 50 अरब डॉलर की बचत हो रही है। संप्रग के अंतिम दो वर्षों में यहां नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार के कारण भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में 30 अरब डॉलर निवेश किए जाने का अनुमान है। श्री मोदी ने मकड़जाल समाप्त किया और निवेश का माहौल तैयार किया। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आरंभ हुईं, कोयला उत्पादन में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई, बिजली उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई, विश्व मंच पर भारत की छवि में सुधार आया। उम्मीद एवं आकांक्षाओं का सृजन तस्वीर में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा कारक रहा। कार्य के प्रति गंभीर होने की सरकार की छवि ने सब कुछ बदल दिया।

यह बजट इसी रवैये, इसी बदलाव की बात करता है। चार मेगा पावर प्लांट जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, राज्यों में एम्स, आईआईटी तथा आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों का वायदा तो है, लेकिन पूरा ध्यान वायदों पर नहीं बल्कि कार्य करने पर है। यही कारण है कि महाशक्ति बनने का भारत का अविश्वसनीय सपना अब विश्वसनीय और संभव लग रहा है। आयकर की सीमा बढ़ाई जा सकती थी। ईमानदार आयकर दाताओं, वेतनभोगी मध्य वर्ग के लिए अधिक रियायतों की संभावना एवं आवश्यकता थी। 14 प्रतिशत सेवा कर उन पर भारी पड़ेगा। कर का दायरा बढ़ाया जाना है। सेवा कर खर्च पर नजर रखने का आधुनिक उपकरण है। लेकिन इसके लिए वेतनभोगी वर्ग को अधिक रियायतें दिया जाना बेहतर है। उसके अलावा श्री जेटली के बजट ने सभी को संतुष्ट किया है।

संप्रग ने 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, जिसमें महंगाई की दर 12 प्रतिशत से अधिक थी, ब्याज दर 13 प्रतिशत थी, खाद्य महंगाई दहाई अंकों में थी, बेरोजगारी 10 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ रही थी, शेयर बाजार लुढ़क रहे थे, काला धन बढ़कर जीडीपी के 71 प्रतिशत के बराबर हो गया था और अर्थव्यवस्था ठहरी हुई थी। निवेशक भारत में आने से डर रहे थे क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सरकारी फाइलों में अटके थे। अफसरशाह निर्णय नहीं ले रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय कमजोर था और उनका बचाव नहीं कर सकता था।

श्री नरेंद्र मोदी ने यह सब बदल दिया और व्यवस्था में गति तथा स्फूर्ति लाए। बजट उसी ऊर्जा और उत्साह का परिणाम है। इसमें वृद्धि का ध्यान रखा गया किंतु यह भी सुनिश्चित किया गया कि समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर दुर्बल वर्ग की रक्षा हो। बजट मोदी के वोट बैंक को प्रसन्न रखने और नए वर्गों तक पहुंचने की मजी हुई कवायद है। पूर्वोत्तर एवं जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान भारत को अखंड बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम है। स्वच्छ शहरों, विश्वस्तरीय सुविधाओं एवं तीर्थाटन पर जोर देने से पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार सृजन होगा तथा कीमती विदेशी मुद्रा आएगी।

बुनियादी ढांचे पर खर्च, 100 नए शहर एवं विशेष औद्योगिक

शृंखलाएं अर्थव्यवथा को प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगी। अब तक हाशिये पर डाले गए किसानों पर विशेष ध्यान देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। आर्थिक विकास के इंजन की गति परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में होगी और बजट की व्यावहारिकता एवं दूरदर्शिता इस मामले में आश्वस्त करती है। यहीं पर मोदी की छाप है, जो वही कहते हैं, जो संभव है। बजट ने उन सभी बड़े सपनों की बात की है, जिन्होंने भाजपा को आश्चर्यजनक सफलता दिलाई। मेरी आंखों के सामने यह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ बजट है। यह नेहरूवादी आलस्य को विदाई और एक नए भारत, एक विश्व शक्ति की अंगड़ाई है।

जन सुरक्षा (असुरक्षितों को सुरक्षित करना)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (बैंकों से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देना)

सरकार ने एक सोची समझी योजना के अंतर्गत जन धन योजना आरंभ की, जिसका मूल उद्देश्य सभी को बैंक खाते उपलब्ध कराना है। विश्व रिकॉर्ड बनाते हंए 15 करोड़ बैंक खाते खोले गए और सरकारी बैंकों ने 13.4 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए। योजना में आरंभ में पहले वर्ष के लिए 1 लाख रुपये के निःशुल्क दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये के निःशुल्क जीवन बीमा योजना का भी प्रावधान है। इन खातों में 15,800 करोड़ रुपये जमा हुए। बैंक में खाता खोलकर सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को उनकी मेहनत से कमाई और बचाई रकम अनधिकृत, जोखिम भरी योजनाओं में लगाने से रोक लिया।

मुद्रा बैंक (वित्तीय सहायता से वंचितों की मदद)

20,000 करोड़ रुपये की निधि से आरंभ की गई यह योजना छोटे उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण दिलाती है। यह योजना छोटे उद्यमियों की बड़ी सहायता करेगी, जिन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है और दुष्चक्र में फंसना पड़ता है। लालफीताशाही को दूर कर 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण आसानी से दे दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना से 6 करोड़ इकाईयों वाले असंगठित क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है, जिनमें 60 प्रतिशत इकाईयां अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों की हैं।

गरीबों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा की दिशा में पहला कदम

उन परिवारों, जिनके मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई अथवा वे पूर्ण रूप से अशक्त हो गए, उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तीन योजनाएं आरंभ की हैं। तीनों योजनाएं आरंभ होने के बाद पहले सप्ताह में ही 6.75 करोड़ से अधिक लोगों ने इनमें पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 90 पैसे प्रतिदिन अथवा 330 रुपये प्रतिदिन के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा देती है। 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले लोग यह बीमा करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल 1 रुपये प्रतिमाह (12 रुपये प्रतिवर्ष) के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा देती है। 18 से 70 वर्ष तक की आयु वाले लोग यह बीमा करा सकते हैं।

अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी देती है, जिसमें उन लोगों पर ध्यान है, जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार पांच वर्ष तक प्रीमियम की आधी रकम देगी, जो अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिवर्ष तक होगी।

भरोसा – लोगों पर विश्वास करने वाली सरकार

सरकार ने सैकड़ों पुराने कानून खत्म कर दिए, जिससे आम आदमी को बहुत मदद मिली। 125 कानून बदल दिए गए हैं और 1,234 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए पहचाना गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण नियम खत्म किया गया है, वह है सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापन की आवश्यकता। अब स्वयं सत्यापन की अनुमति दे दी गई है, जिसे नागरिकों को अपने दस्तावेज स्वयं ही सत्यापित करने का अधिकार मिल गया है। बॉयलर के निरीक्षण से लेकर श्रम अनुपालन रिपोर्ट तक स्वयं प्रमाणन का अधिकार दे दिया गया है। जीवन बीमा पोर्टल – आधार कार्ड से संचालित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र और झंझट रहित बायो–मीट्रिक पेंशन प्रमाणन ने 1 करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों की सहायता की है। 4 महीनों में 1 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। इंटरनेट पर आधारित संवाद योजना माईगॉव नागरिकों को सहभागिता वाले प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कहता है।

सुशासन – पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार

भाजपा ने काले धन से लड़ने के अपने वायदे पर काम किया है। इसने काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है, जो सरकार का पहला फैसला था। कर चोरी करने वालों के लिए कठोर काला धन कानून पारित किया गया। कठोर दंड (10 वर्ष तक के लिए सश्रम कारावास समेत) के प्रावधान किए गए। कर से मुकरने वालों और विदेश में अवैध खाते रखने वालों पर त्वरित कार्रवाई आरंभ की गई। भाजपा की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि रही कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित नीलामी तथा आवंटन, जिससे (रद्द हुए 204 ब्लॉकों में से) 67 ब्लॉकों से कुल 3.35 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। कोयला नीलामी एवं आवंटन से हुई प्राप्तियां कोयला भंडार वाले राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि को जाएंगी। इसी प्रकार स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकारी खजाने में 1.09 लाख करोड़ रुपये आए, जबकि संप्रग सरकार ने उसका मूल्य शून्य लगाया था। भेदभाव वाली प्रणाली हटाकर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक नीलामी प्रक्रिया अपनाते हुए खान अधिनियम को आधुनिक बनाया गया है।

एलईडी बल्बों की पारदर्शी खरीद के कारण कीमत में 74 प्रतिशत कमी होने (310 रुपये से घटकर 82 रुपये) से सीधे जरूरतमंद लोगों को फायदा हुआ। सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही हैं। बिचौलियों को हटाकर, भ्रष्टाचार मिटाकर, बचत को सही जगह लगाकर सही समय पर सही हाथों में सही मात्रा में सब्सिडी देना इस योजना की विशेषता है। रसोई गैस सब्सिडी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना पहल रिकॉर्ड समय में आरंभ की गई और 13 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई। स्वतः लेन देन के माध्यम से जनवरी 2015 से 11,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच चुकी है। जैम (जन धन, आधार एवं मोबाइल) की सहायता से डीबीटी को पेंशन तथा छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं में भी धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।

स्किल इंडिया

कौशल विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय आरंभ किया गया

है। निगरानी वाली विश्वसनीय व्यवस्था में योग्य युवाओं का कौशल विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल अभियान और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति तैयार की गई है। अब तक 76 लाख युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। 'स्कूल टू स्किल' कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रमाणन को शैक्षिक प्रमाणन जितनी मान्यता दी गई है। 1,500 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। 3 वर्ष में 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तैयार की गई है। अप्रेंटिसशिप कानून में संशोधन किए जा रहे हैं ताकि नौकरी करते हुए प्रशिक्षण के अधिक अवसर मिल सकें। ई-प्रमाणन और 11,000 से अधिक सूचनाओं के एक समर्पित पोर्टल आरंभ किया गया है।

शिक्षित भारत – स्वयं

विशाल खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भाजपा सरकार ने ऑनलानइन शिक्षा को सबल बनाने में भारी सहयोग किया है। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन आरंभ किया गया। बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए विशिष्ट योजना उड़ान आरंभ की गई है। दुनिया भर से ज्ञान ग्रहण करने में छात्रों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय की परियोजना आरंभ की गई है। यह सभी को शैक्षिक सामग्री और ज्ञान के स्रोत उपलब्ध कराती है। भाजपा सरकार अब ज्ञान (ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ अकेडमिक नेटवर्क) में भी व्यस्त है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों से प्रसिद्ध शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भारत लाया जाएगा। भाजपा सरकार ने 5 नए आईआईटी और 6 नए आईआईएम समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले कई संस्थान खोलने की घोषणा भी की है। छात्रों को केंद्र सरकार की योजनाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम समग्र कार्यक्रम है, जो छात्रों को ऋण प्राप्त करने में मदद करता है।

सर्वे संतु निरामया – सभी को स्वास्थ्य का आश्वासन

भाजपा सरकार ने 10 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

खोलने की योजना तैयार की है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली में जीवन रक्षक दवाओं की संख्या दोगुनी (अब 330) कर दी गई है। औषधि क्षेत्र के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय पोर्टल आरंभ किया गया है। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने के लिए सरकार ने इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम नेशनल डीवॉर्मिंग डे आरंभ किया। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए नवजात कार्य योजना आरंभ की गई है। डायरिया पर नियंत्रण के लिए स्वच्छता अभियान के साथ स्वदेश में विकसित पहला रोटावायरस टीका उतारा गया है। नए टीकों – मीजेल्स रुबेला, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) और वयस्कों के लिए जापानी इनसिफेलाइटिस के साथ टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और उसमें सुधार किया गया है।

मिशन इंद्रधनुष

भाजपा सरकार ने 2020 तक 89 लाख से अधिक बच्चों को टीकाकरण के जरिये 7 बीमारियों से बचाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में 35 लाख बच्चों को नवगठित आयुष मंत्रालय द्वारा पहले ही टीका दिया जा चुका है। सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन भी आरंभ किया है, जिसमें चिकित्सा की सभी पारंपरिक भारतीय पद्धतियों को शामिल किया गया है। 177 देशों से समर्थन जुटाकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।

स्वच्छ भारत अभियान

भाजपा सरकार के लिए स्वच्छ भारत एक राष्ट्रीय अभियान है। इसे भारत की जनता की सहभागिता के इरादे से तैयार किया गया है। अभियान के अंतर्गत 2014–15 में 58 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। 2019 तक 6.6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए भारत सरकार गरीबी की रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपये देकर व्यक्तिगत शौचालय बनाने में सहायता कर रही है। भाजपा सरकार ने साल भर में देश के सभी स्कूलों में शौचालय बनाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। नमामि गंगे भी गंगा को स्वच्छ करने और उसका वैभव वापस लाने के प्रयास वाला राष्ट्रीय अभियान है। गंगा की सफाई के लिए

20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गंगा के किनारे औद्योगिक प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी आरंभ की गई है और वाराणसी में घाटों की सफाई तेजी से चल रही है।

धरती की धरोहर – बेहतर गृह निर्माण

भाजपा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि उसमें सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है। सीएएमपीए कानून के अंतर्गत वनारोपण हेतु राज्यों को 38,000 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। बिजली से चलने वाले दो, तीन और चार पहिया वाणिज्यिक वाहनों को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। विलंब और पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरियां ऑनलाइन दी जा रही हैं।

अंतरिक्ष

भारत पहले ही प्रयास में मंगल अभियान में सफल होने वाला पहला देश है। भाजपा सरकार के नेतृत्व में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की प्रायोगिक उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी (जीसैट एमके–3) का परीक्षण सफल रहे। नागरिक विमानों को मार्ग बताने वाली भारतीय उपग्रह आधारित सेवा गगन पूरी तरह आरंभ हो गई है और भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इन्नोवेशन मिशन (एम) और सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन (सेतु) आरंभ की गई हैं।

डिजिटल इंडिया

सभी को डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का यह कार्यक्रम भाजपा सरकार एक और प्रगतिशील कदम है। इसके तहत विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। वेब पोर्टल माईगॉव इकलौता सूचना पटल बन गया है। जीवन प्रमाण पोर्टल, डिजिटल लॉकर, ई–साइन फ्रेमवर्क स्पेस जैसे नागरिकों के अनुकूल कदम लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किए गए हैं।

सह ना वदतु – सबल भारत, सुरक्षित भारत

भारत की सुरक्षा एवं अखंडता के मामले में कोई समझौता नहीं करने के भाजपा के रुख के अनुसार सरकार ने रक्षा उपकरणों के

स्वदेश में निर्माण की नीति को मंजूर किया है, एफडीआई नियमों में ढील दी है, जिससे एयरबस और बोइंग ने भारत में विमानों के पुर्जे बनाने की घोषणा की – रूसी हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाने का प्रस्ताव है, अमेरिका के साथ सह–उत्पादन की चार परियोजनाएं हैं, वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ाई जा रही है, फ्रांस से 36 रफायल जेट खरीदने का समझौता किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है।

सेवा परमो धर्मः – आवश्यकता के समय में राहत

देश में किसानों की आत्महत्या का प्रमुख कारण था आपदा एवं फसल बर्बाद होने की स्थिति में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होना। भाजपा सरकार ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों के लिए राहत की योजना तैयार की है। जब भी भारत की जनता का जीवन या संपत्ति खतरे में पड़ती है जैसे जम्मू–कश्मीर में बाढ़, कोसी बाढ़ और हुदहुद चक्रवात तो राज्य की सहायता करने के अलावा केंद्र सरकार सीधे भी सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार विदेश में काम कर रहे भारतीयों का जीवन भी भाजपा सरकार के लिए उतना ही कीमती है। अंतरराष्ट्रीय संकट के समय उसने प्रभावी तरीके से कार्य किया, चाहे नेपाल भूकंप में 15,500 भारतीयों और 33 अन्य देशों के 170 नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री हो या यमन में 4,700 भारतीयों और 48 अन्य देशों के 1,900 नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत हो या यूक्रेन से 1,000 से अधिक भारतीय छात्रों को, लीबिया से 3,300 भारतीयों को तथा इराक से नर्सों समेत 7,000 भारतीयों को निकालना हो।

वसुधैव कुटुंबकम्

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के बाद 50 वैश्विक नेताओं से भेंट कर चुके हैं। भारत ने हिंद महासागर के लिए इंडियन ओशन विजन और सक्रिय एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मंजूरी देने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने पड़ोसियों के साथ संपन्नता – सार्क उपग्रह, सार्क आपदा प्रबंधन साझा करने का प्रस्ताव किया है।

विकास तथा सामरिक सहयोग के लिए दक्षेस

भारत के इतिहास में अनूठा क्षण है, जहां से वह विश्व नेता के

रूप में उभर सकता है। पिछले चुनावों में भाजपा को जो स्पष्ट जनमत मिला और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तथा सर्वमान्य विश्व नेता बनकर उभरे, उससे भारत के आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव में विस्तार का नया युग आरंभ हुआ है। कार्यभार संभालने के फौरन बाद श्री मोदी ने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध सुधारने के प्रयत्न आरंभ कर दिए।

उनकी पहली आधिकारिक यात्रा भूटान की थी और उसके बाद उन्होंने नेपाल की सफल यात्रा की। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभी दक्षेस नेताओं की उपस्थिति ऐसी घटना थी, जिसने अधिक फलदायी क्षेत्रीय सहयोग की नींव रखी। स्वतंत्रता दिवस पर अपने ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री ने आर्थिक एवं व्यापारिक संधियों की तथा क्षेत्र में मौसम की निगरानी, संचार के प्रसार और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु सार्क उपग्रह की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबी तथा रोगों से लड़ने के लिए देशों को हाथ मिलाने होंगे। दक्षेस के स्वाभाविक नेता के रूप में भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने में भूमिका निभानी है। क्षेत्र में अधिकतर देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते हैं और भारत ने पाकिस्तान को सबसे देश का दर्जा दिया है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी भारत को यह दर्जा नहीं दिया है।

विश्व शक्ति बनने की देहरी पर खड़ा भारत द्विपक्षीय टकरावों में नहीं फंस सकता। पाकिस्तान असफल देश है। यूरोप में लगातार आर्थिक पराभव हो रहा है। अमेरिका अपनी ही परेशानी में फंसा है। उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा और उसकी विदेश नीति खस्ता हालत में है। चीन में मंदी आ रही है, जापान तीन दशक लंबी मंदी से उबर रहा है। कई पाश्चात्य अर्थशास्त्री जिस ''पूंजी'' को विकास का एकमात्र कारक बताते हैं, उसकी पूर्व में कोई कमी नहीं है और पश्चिम में वह दुर्लभ होती जा रही है। यह शताब्दी पूर्व की शताब्दी है।

इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पश्चिम अपनी धार खो चुका है। वित्तीय जगत में 2008 के आर्थिक विनाश के बाद प्रकाशित कई पुस्तकों, लेखों में विस्तार से बताया गया है कि पश्चिम ने अपना आर्थिक लाभ किस प्रकार गंवाया। औपनिवेशीकरण और विश्व युद्धों को पाश्चात्य अर्थव्यवस्था ने आगे बढ़ाया। यदि हम विश्व

के आर्थिक इतिहास के दो हजार वर्षों को देखें तो हम पाएंगे कि पश्चिम का आर्थिक दबदबा केवल दो सौ वर्षों के लिए रहा और बाकी 1800 वर्ष भारत, चीन तथा जापान के रहे। एंगस मैडिसन ने अपने विश्व प्रसिद्ध आर्थिक आंकड़े प्रकाशित किए, जिनमें प्राचीन दुनिया के यूरोप से लेकर भारत से लेकर चीन से लेकर जापान और बाद में अमेरिका तक 1500 वर्ष के विकास, जनसंख्या तथा बुनियादी ढांचा विस्तार के अनुमान हैं। मैडिसन के आंकड़ों में उल्लेखनीय बात यह है कि वे कितने भी पीछे जाएं, केवल विश्व अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की बात नहीं करते बल्कि यह भी बताते हैं कि एक-दूसरे की तुलना में वे कितना बढ़ीं अथवा कम हुईं। अध्ययन के अनुसार 1820 के दशक में विश्व जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी 32.4 प्रतिशत थी, जबकि यूरोप की 26.6 प्रतिशत एवं अमेरिका की 1.8 प्रतिशत थी। 1700 के दशक में चीन और यूरोप की जीडीपी हिस्सेदारी 23-23 प्रतिशत थी और उस समय यूरोप द्वारा एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका का औपनिवेशीकरण चरम पर था। प्लासी के युद्ध के 63 वर्ष बाद 1820 में भी भारत की जीडीपी हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी।

प्रसिद्ध इतिहासकार विल ड्यूरंट अपनी पुस्तक 'अ केस फॉर इंडिया' में विस्तार से बताते हैं कि यूरोप तथा इंगलैंड ने किस तरह भारत को लूटा और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। एक अन्य आर्थिक इतिहासकार डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो अपनी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकनॉमी में कहते हैं कि कपड़ा बाजार पर भारत का हजारों वर्षों का जो वर्चस्व था, उसे तोड़ने के लिए बराबरी का कपड़ा तैयार करने में अंग्रेजों को 200 वर्ष लग गए और ऐसा प्लासी के युद्ध के बाद लूटे गए धन से ही संभव हो सका।

कहने का अर्थ यही है कि भारत का समय आ गया है। क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए इसे म्यांमार समेत दक्षेस क्षेत्र की ओर देखना होगा। इसके साथ ही उसे अपने भीतर भी देखना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे हैं, भारत के पास लोकतंत्र (डेमोक्रेसी), जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और मांग (डिमांड) की 3डी ताकत है।

श्री मोदी ने कूटनीति को आर्थिक सहयोग के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया है। पिछले एक वर्ष और कुछ महीनों में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के प्रयास किए, जिसे संप्रग के दस वर्ष के

शासन में बहुत धक्का लगा था। इस दशक में सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ गए। दुनिया में भारत की छवि खराब हुई और भारत से 20 अरब डॉलर का निवेश तो केवल अमेरिका में ही चला गया। श्री मोदी के प्रयास भारत में कारोबार करने में आने वाली बाधाएं दूर करने, देश से पूंजी का पलायन रोकने और बुनियादी ढांचा सुधारने के हैं। भारत के भाग्य से कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि अमेरिका से मांग घट रही है और अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे तेल उत्पादक देश अपनी विदेशी मुद्रा की समस्याओं से निपटने के लिए अधिक से अधिक तेल उत्पादन कर रहे हैं।

गोल्डमैन सैक्स की ब्रिक्स रिपोर्ट का अनुमान है कि यदि भारत वर्तमान दर से विकास करता है तो तो 2035 तक वह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी के नेतृत्व में भारत का माहौल पहले ही बदल चुका है।

जापान, चीन, वियतनाम और म्यांमार जैसे एशियाई देश भारत के साथ अपने आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जापान और चीन ने मिलकर भारत में 60 अरब डॉलर के निवेश के समझौते किए हैं। रक्षा एवं विमानन क्षेत्र में उदारीकरण से और अधिक निवेश आने का अनुमान है।

इस परिस्थिति में भारत दक्षेस को अधिक आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बनाना चाहेगा। म्यांमार में भारत के लिए तेल तथा गैस सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। कपास तथा कपड़ा भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए विकास के क्षेत्र हैं। श्री मोदी ने नेपाल तथा भूटान में विशेषकर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग तथा निवेश के लिए ठोस बुनियाद डाली है। प्रत्येक पड़ोसी विकास करते भारत का घनिष्ठ सहयोगी बनना चाहेगा। पाकिस्तान हमेशा अलग-थलग रहेगा। उपमहाद्वीप में जब तक आतंक, काले धन को सफेद बनाने, नशे की तस्करी करने और राज्य प्रायोजित आतंकवाद जैसी बातें रहेंगी, तब तक साझा मुद्रा, साझा बाजार और सबसे तरजीही देश की संधियां भी कठिन होंगी।

भाजपा सरकार ने दशकों पुराने मुद्दे का स्थायी समाधान करते हुए बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसे लागू किया। विदेश में बसे भारतीयों के लिए लाभ

बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने कई अनूठी पेशकश की हैं। उनमें से कुछ हैं। ओसीआई और पीआईओ योजनाओं का विलय, पीआईओ को आजीवन वीजा देना, पुलिस के पास सूचना देने की अनिवार्यता समाप्त करना, शिकायतें दूर करने के लिए मदद पोर्टल आरंभ करना। इतने देशों के साथा भाजपा सरकार के सकारात्मक संवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वैश्विक रुचि जगा दी है – अमेरिका से 42 अरब डॉलर, जापान से 35 अरब डॉलर, चीन से 20 अरब डॉलर के निवेश की योजना। स्किल इंडिया के लिए अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के साथ समझौते किए गए हैं।

अष्टलक्ष्मी – पूर्वोत्तर का विकास

भाजपा पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास एवं प्रगति की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देने के लिए केंद्रीय बजट में 53,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) 'डिपार्टमेंट एट योर डोरस्टेप' कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रियता के साथ प्रत्येक राज्य की राजधानी में पहुंच रहा है। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना 'ईशान उदय' की घोषणा की गई है। मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और पूर्वोत्तर में 6 नए कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। सरकार ने प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में परिधान उत्पादन केंद्र स्थापित करने का भी ऐलान किया है, जिनमें से नगालैंड, मणिपुर और सिक्किम में कार्य आरंभ हो चुका है। समग्र पारेषण एवं वितरण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

नगर–शहर, विकास की लहर – शहरी कायांतरण

भाजपा के घोषणा पत्र में शहरी भारत की सूरत बदलने का वायदा किया गया था। इसके लिए स्मार्ट सिटी एवं शहरी कायांतरण (अमृत – अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) कार्यक्रम के लिए 98,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। नागपुर और अहमदाबाद के लिए नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में मेट्रो रेल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। लखनऊ और पुणे के लिए मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।

तमसो मा ज्योतिर्गमय – सभी के लिए बिजली

भाजपा सरकार ने करोड़ों जिंदगियों को प्रकाशित करते हुए चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) एवं शहरी (एकीकृत विद्युत विकास योजना) क्षेत्रों के लिए समर्पित योजनाएं आरंभ की हैं। कोल इंडिया के उत्पादन में 3.2 करोड़ टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक 22,500 मेगावाट की वृद्धि की योजना बनाई है। इस वर्ष में ऊर्जा की कमी भी 3.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम रही। बिजली उत्पादन में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो दो दशक में सबसे तेज वृद्धि है। सरकार ने एक वर्ष में सबसे अधिक 3,600 करोड़ यूनिट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ समझौतों के माध्यम से असैन्य परमाणु सहयोग का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय ग्रिड (पारेषण) को अभूतपूर्व बल दिया गया है और 2015 तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया गया है और एक वर्ष के भीतर 100 शहरों को एलईडी से प्रकाशित करने का लक्ष्य है। 2022 तक 175 गीगावाट के लक्ष्य के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की गई है।

परिवहन से परिवर्तन

रेलवे – भारत की जीवनरेखा पटरी पर लौट आई है। रेलवे स्टेशनों पर वाई–फाई, यात्री हेल्पलाइन (138), सुरक्षा हेल्पलाइन (182), कागज रहित अनारक्षित टिकट, ई–केटरिंग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल सुरक्षा एप और सीसीटीवी कैमरे जैसी यात्रियों के अनुकूल कई सुविधाएं आरंभ की गई हैं। अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में रेलवे ने राज्यों (जैसे झारखंड, ओडिशा) के साथ विशेष उपक्रमों के माध्यम से खानों, समुद्र तटों आदि से जोड़ा है और मुंबई–अहमदाबाद गलियारे के लिए तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की योजना बनाई गई है। नई दिल्ली–चेन्नई मार्ग के लिए भी व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। 1,983 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का कार्य आरंभ किया जाना और 1,375 किमी लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना उल्लेखनीय प्रदर्शन है। तीर्थाटन के लिए 6 नई गाड़ियां आरंभ की गईं और वैष्णोदेवी रोडवेज तक यात्रा के लिए

कटरा लाइन खोल दी गई।

परिवहन क्षेत्र को सुचारु बनाने के लिए भाजपा सरकार ने कई फंसी हुई सड़क परियोजनाएं आरंभ कीं, ठेका संबंधी पुराने विवाद सुलझाए और अव्यावहारिक परियोजनाएं खत्म कर दीं। एक नया प्रयास भारत माला आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत भारत की सीमा पर सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 62 टोल प्लाजा पर टोल शुल्क संग्रह बंद किया गया है और 300 प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली आरंभ की गई है। भाजपा सरकार ने सड़क सुरक्षा को तुरंत महत्व देते हुए दुर्घटना हाने पर नकदरहित उपचार, सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और सार्वजनिक परिवहन की वीडियो रिकॉर्डिंग की घोषणा की।

नागर विमानन – सपनों को पंख

मोहाली, तिरुपति और खजुराहो में नए एकीकृत टर्मिनल की इमारतों का निर्माण पूरा होने वाला है। कडप्पा और बीकानेर में टर्मिनल पूरे हो चुके हैं। क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हुबली, बेलगाम, किशनगढ़, तेजू और झारसुगुडा में हवाई अड्डों का उन्नयन आरंभ हो गया। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा जांच (आईएएसए) को एफएए द्वारा ऊंची सुरक्षा रेटिंग दी गई, जिससे अधिक उड़ानें संचालित हो सकीं। एयर इंडिया विमान कंपनियों के सबसे बड़े गठबंधनों में गिने जाने वाले प्रतिष्ठित स्टार अलायंस में शामिल हो गई है।

श्री मोदी उठा रहे हैं प्रवासियों की 'पूंजी' का लाभ

श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संबंध में प्रवासी भारतीयों का दृष्टिकोण बदल दिया है। भारत का कोई भी अन्य प्रधानमंत्री भारतीयों को अपने मूल स्थान के प्रति गौरवान्वित नहीं कर सका और उनमें वापस आने की इच्छा नहीं जगा सका। यह पिछले सात महीनों में संभवतः उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अमेरिका का कोई अन्य राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि नहीं बना। केवल श्री मोदी ही सोच सकते थे कि इस कदम का भारत के बारे में अन्य देशों के नजरिये पर कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण है कि पिछले भारतीय

प्रधानमंत्रियों ने भारतीय गणतंत्र दिवस को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा? भारत उभरती हुई महाशक्ति है, यह एक बात है। वह अगले दो दशकों में संभवतः सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, जैसा गोल्डमैन सैक्स और अन्य अध्ययनों में दिखता है, यह दूसरी बात है। किंतु असली बात यह है कि मोदी ने भारत के बारे में दुनिया भर के नजरिये को किस तरह प्रभावित किया है।

आधुनिक कूटनीति काफी हद तक नजरिये पर ही निर्भर करती है। संचार क्रांति ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन का व्याकरण नए सिरे से लिख दिया है और श्री मोदी इस कला में पारंगत हैं।

प्रवासी भारतीय कारोबारियों के लिए भारत एक बार फिर पसंदीदा निवेश स्थल बन रहा है। श्री मोदी ने तेजी से वह सब कर दिया है, जिसमें उनके पूर्ववर्ती असफल रहे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को आश्वस्त कर दिया है कि भारत को उनकी चिंता है। उनकी कई पुरानी मांगें जैसे स्थायी वीजा, आव्रजन कानूनों का सरलीकरण, मताधिकार पर आश्वासन, संपत्ति के स्वामित्व, निवेश एवं मुनाफे को स्वदेश भेजने की अनुमति देना आदि को उन्होंने थोड़े-थोड़े से अंतराल पर स्वीकार कर लिया। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बांहें फैलाकर उनका स्वागत किया है। अधिक स्थायी योगदान है भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को प्रवासी भारतीयों के लिए अधिक सहायक बनाना। ये प्रतिष्ठान अलग-थलग रहते थे और कारगर नहीं थे। श्री मोदी के नेतृत्व में वे आर्थिक कूटनीति एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र बन गए हैं।

विश्व स्तर पर भारत के छवि निर्माण में 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों की असीम कूटनीतिक क्षमता को श्री मोदी समझ चुके हैं। श्री मोदी सदैव प्रवासी भारतीयों के दुलारे रहे हैं। पिछले दशक में सभी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों में वह सर्वाधिक चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रियों पर भी भारी पड़े हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जब इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। जब आप गूगल पर 'NRI+Modi' टाइप कर खोजेंगे तो रिकॉर्ड 31,30,000 परिणाम आएंगे, जो स्वयं ही एनआरआई-मोदी घनिष्ठता

का सूचक है। वे धीरे–धीरे भारत के भाग्य में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। बराक ओबामा जैसे विश्व नेताओं को मोदी के करीब खड़े होने से लाभ मिलेगा क्योंकि इस वर्ष चुनावों में उनके गृह क्षेत्र में राजनीतिक संदेश जाएगा। आव्रजक मतदाताओं को बड़े यत्न से लुभाया जाता है और वे परिणाम पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। श्री मोदी के मैडिसन स्क्वायर कार्यक्रम के बाद, जिसमें तीन दर्ज सीनेटर उपस्थित थे, ओबामा ने आव्रजन कानून नरम बना दिए, जिससे भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और कुशल कामगारों को मदद मिली। भारत अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में छात्र भेजता है। मोदी लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

स्वराज्य से सुराज – सुशासन प्रदान करना

सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद के माध्यम से टीम इंडिया तैयार करना ही भाजपा के लिए प्रशासन का मंत्र रहा है। केंद्र ने राज्यों को सौंपे जाने वाले धन में 10 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि की है। कोयले तथा अन्य खनिजों की नीलामी प्रक्रिया में सुधार कर और भी धन दिया जा रहा है। केंद्र तथा राज्यों के बीच योजना से लेकर नीतियों तक वास्तविक साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। सरकार के खर्चों को तर्कसंगत बनाने के लिए व्यय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून तैयार किया जा रहा है। सरकार ने संसद की रिकॉर्ड कार्य क्षमता – दशक में सर्वाधिक बैठक हुई और 47 विधेयक पारित हुए (6 वर्ष में सर्वाधिक) – भी सुनिश्चित की है।

नौवहन – विकास की दिशा में जलयात्रा

जीवंत तटवर्ती समुदायों के विकास के माध्यम से बंदरगाह आधारित समग्र विकास के लिए सागरमाला परियोजना आरंभ की गई। बंदरगाहों पर कार्गो अर्थात् माल ढुलाई की वृद्धि दर दोगुनी होकर 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत पर पहुंच गई। प्रमुख बंदरगाहों पर वार्षिक क्षमता में सर्वाधिक 7.1 करोड़ टन वृद्धि दर्ज की गई। चाबहार बंदरगाह के कूटनीतिक विकास के लिए तथा अफगानिस्तान एवां मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए ईरान के साथ समझौता

किया गया है। गंगा के रास्ते ढुलाई तथा जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना आरंभ की गई है।

तेज गति, आर्थिक प्रगति – जीवंत अर्थव्यवस्था

भाजपा को महंगाई पिछली सरकारों से विरासत में प्राप्त हुई है। लगभग 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने करोड़ों परिवारों, विशेषकर गृहिणियों को राहत देते हुए बेलगाम कीमतों को काबू में लाने का अपना वायदा पूरा किया है। पिछले वर्ष मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट देखने को मिली है। सीपीआईः अप्रैल 2014 के 8.5 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2015 में 4.9 प्रतिशत। सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीतिः अप्रैल 2014 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2015 में 5.1 प्रतिशत। सीपीआईः अप्रैल 2014 में 5.6 प्रतिशत और अप्रैल 2015 में (–)2.6 प्रतिशत।

जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कठोर दंड के साथ सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकारी भंडार से 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज जारी किया गया है। कुछ निश्चित जिंसों के मूल्यों में अधिक उतार–चढ़ाव रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। राज्यों के बीच फलों और सब्जियों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देकर सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे बाजार में बेचने के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। गेहूं, प्याज और दालों पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया। चावल, उड़द और तुअर के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। आज भारत 7.4 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रमुख रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एडीबी, ओईसीडी, अंकटाड, एसएंडपी, फिच और मूडीज ने बहुत बेहतर रेटिंग दी हैं। मेक इन इंडिया अभियान निवेश आकर्षित कर रहा है, जिसमें एफडीआई और एफआईआई आ रहा है। भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ आर्थिक सुधार हैंः रक्षा, बीमा और पेंशन में 49 प्रतिशत एफडीआई, रेलवे में 100 प्रतिशत एफडीआई, निर्माण के नियमों में ढील, डीजल की कीमतों से अंकुश हटाना, लोकसभा में जीएसटी पारित होना, जो 1947 के बाद से सबसे बड़ा कर सुधार है, देसी सामान को आयातित सामान से महंगा बनाने वाली कर संबंधी विसंगतियां काफी हद तक दूर कर दी गई हैं, कई सार्वजनिक उपक्रमों की सेहत ठीक कर दी गई है, एक ही वर्ष में 24,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश

किया गया है। इन सुधारों के साथ ही मध्य वर्ग को कर में राहत दी गई है। कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 4.44 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे प्रति वर्ष 40,000 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। चिकित्सा बीमा की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपये) कर दी गई है। वरिष्ठ बीमा योजना को सेवा कर से छूट दे दी गई है।

हर हाथ को काम – सभी के लिए रोजगार

मेक इन इंडिया

बड़े स्तर पर उत्पादन तथा भारी संख्या में कामगारों द्वारा उत्पादन के लिए आरंभ मेक इन इंडिया युद्ध स्तर पर चल रहा है। भाजपा सरकार ने निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ के गठन के द्वारा, एक ही फॉर्म के माध्यम से सभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए ई–बिज पोर्टल बनाकर, आयात–निर्यात की औपचारिकताएं घटाकर, उद्योग से लाइसेंस प्रणाली तथा नियमन हटाकर और बौद्धिक संपदा की संरक्षा कर व्यापार की सुगमता सुनिश्चित की है।

टेक्सटाइल (वस्त्र)

20 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनसे 66,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन रिटेलिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे हस्तशिल्प निर्यात में 20 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। जम्मू–कश्मीर में पश्मीना कारीगरों के कल्याण के लिए योजना आरंभ की गई। 44 लाख परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए जूट की बोरियों में खाद्यान्न की पैकिंग अनिवार्य कर दी गई।

पर्यटन

भाजपा सरकार ने पर्यटन को ऐसे क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है, जो भारत में विदेशी मुद्रा ला सकता है, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। 76 देशों के पर्यटकों को वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन 'ई–वीजा' की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1.2 लाख से अधिक ई–वीजा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 74 अन्य देश चिह्नित किए गए हैं। प्रमुख स्मारकों – ताज महल और हुमायूं का मकबरा के लिए ई–टिकटिंग आरंभ कर दी गई है। प्रसाद

(पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटेशन ड्राइव) आरंभ किया गया है, जिसमें एकीकृत विकास के लिए 12 तीर्थस्थलों – वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, मथुरा, गया, कांचीपुरम, वेलंकन्नी, द्वारका, पुरी, अमरावती, केदारनाथ और कामाख्या को चुना गया है।

यह तो केवल आरंभ है... हम जीवंत, समृद्ध और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके स्तंभ होंगेः हर खेत को पानी के बल पर फलती–फूलती कृषि, हमारे युवाओं को सशक्त कर सबके लिए रोजगार की ओर ले जाना, सबके लिए आवास के माध्यम से गांवों तथा शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारना, जन धन से जन सुरक्षा और मुद्रा की मदद से वित्तीय समावेशन, स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत के लिए स्वच्छ भारत, चौबीस घंटे बिजली वाला मजबूत बुनियादी ढांचा, ज्ञान के युग में छलांग लगाने के लिए डिजिटल इंडिया, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से जवाबदेही। ❍❍

भाजपा शासित प्रदेश :
पूर्व योजनाओं पर एक नजर

1. हिमाचल प्रदेश :

वर्ष 2011 में भाजपा के शासन काल में हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड बैंक को कार्बन क्रेडिट्स बेचने वाला देश का पहला प्रदेश बना। जैव कार्बन सीडीएम परियोजना ने एक कार्बन सिंक बनाने के अलावा, ज्यादातर अवक्रमित भूमि पर वानिकी वृक्षारोपण के विस्तार से ग्रीन हाउस गैसों को पृथक करने का कार्य किया हैं। इस परियोजना से जल क्षेत्रों में वनीकरण, आजीविका में सुधार, और समुदाय के लिए कार्बन राजस्व पैदा हो रहा है। यहाँ तक की इस समझौते से आने वाले 20 वर्षो में कम से कम 20 करोड़ रूपए का कार्बन राजस्व होने की सम्भावना हैं। और वर्ष 2015 में प्रदेश के 602 गाँव में 50000 से अधिक किसानों को कार्बन राजस्व के तेहत 1.93 करोड़ रूपए मिले हैं। यह प्रदेश में भाजपा सरकार के पूर्व दीर्घदर्शी सुशासन का ही फल हैं।

साथ ही वर्ष 2009 में प्रदेश में भाजपा सरकार ने राज्य को प्लास्टिक-फ्री बनाने के लिए भी अटल प्रयास शुरू किया और हिमाचल प्रदेश देश का पहला प्लास्टिक-बैन करने वाला प्रदेश बना। नतीजतन आज, प्रदेश की राजधानी शिमला प्लास्टिक फ्री शहर बना।

2. उत्तराखंड :

सुशासन सुनिश्चित करने हेतु ही भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राज्यों के विभाजन की अर्जी मंजूर करते हुए, वर्ष 2000 में 3-राज्यों का निर्माण किया, जिसमे से एक उत्तराखंड भी हैं। उत्तराखंड में भाजपा के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं का सफल एवं जुझारू कार्यान्वयन किया। इस सूची में राज्य की स्वास्थ्य नीति उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2007 में सत्ता में आते ही, भाजपा सरकार ने प्रदेश में 'हेल्थ एंड पापुलेशन पालिसी' का कटिबद्धता से

पालन करते हुए पोलियो, लेप्रोसी, मृत्यु दर, पानी से उत्पन्न बीमारियां, आदि पर नियंत्रण तथा प्रजनन दर नियंत्रण नीति भी शामिल थी। सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत ही उत्तराखंड में नेशनल ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन का सक्षम कार्यान्वयन हुआ। नतीजतन राज्य ने हेल्थ इंडीकेटर्स पर कम समय में बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 'हेल्थ कार्ड' सेवा वर्ष 2010 में प्रारंभ की। भाजपा सरकार ने संस्कृत को प्रदेश के दूसरे राजभाषा के रूप में मान्यता दी।

भाजपा के नेतृत्व में मुख्यमन्त्री श्री भगत सिंह कोशियारी हो या श्री बी.सी. खंडूरी, भ्रष्टाचार के प्रति कड़ी लड़ाई लड़ते हुए, 2011 में राज्य में लोकायुक्त की स्थापना करने का एलान किया और राज्य में पर्यावरण मैत्रिक एवं सतत औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी।

3. उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन काल श्री राजनाथ सिंह के शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा माफिया पर नियंत्रण करने हेतु एंटी-कोपिंग एक्ट 1992 पास हुआ। इस एक्ट से प्रदेश में विद्यालयों में होने वाली मास-चीटिंग पर रोक लगाने हेतु, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। प्रदेश में एक आभासी 'धोखाधड़ी सिंडिकेट' जिसमे अधिकारी, शिक्षक, छात्र और यहां तक कि स्थानीय अपराधी सब मिलकर शिक्षा माफिया के रूप में संचालित थे।

श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार ने इस पर सख्ती से कार्यवाही करी, जिस कारण से भाजपा को चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। परन्तु 1998 में वापस शासन में आने के बाद भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सफाई का कार्य भाजपा सरकार ने जारी रखा।

4. राजस्थान :

राजस्थान में गरीबी से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं को लाया, जिनमें से भाजपा शासनकाल में 2005 में आई पालनहार योजना उल्लेखनीय हैं। इस योजना के तहत 500 रूपए प्रति माह अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों के लिए प्रदान की जाती है जिनके माता पिता नहीं हैं या तो अदालत ने मंजूर आजीवन कारावास काट रहे हैं। साथ ही सहायता के रूप में 675 रूपए

प्रतिमाह स्कूल में बच्चे को स्वीकार करने के बाद प्रदान की है। इसके अलावा 2000 रूपए सालाना इन बच्चों के जो भी कपड़े, जूते, मोजे के लिए प्रदान की जाती है। गत वर्षों में राजस्थान में गरीब अनाथ बच्चों के लिए यह एक प्रभावी योजना बनकर उभरी।

राज्य में विकेन्द्रित एवं सतत विकास हेतु वर्ष 2005-06 में 'स्व-विवेक जिला विकास' योजना का शुभारम्भ हुआ, जिसमे लोकल सामुदायिक जरूरतों को रियल-टाइम में पूरा करने हेतु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिये एक उत्तरदायी तंत्र बनाया।

इसी क्रम में 2014 में गठित भाजपा सरकार ने राजस्थान में वित्तीय समावेश हेतु 'भामाशाह योजना' का पुनः शुभारम्भ किया जिसका उद्देश्य केंद्र की जन-धन योजना को सफल बनाने के साथ ही महिलाओं को बैंकिंग सुविधा से सशक्त बनाना हैं।

5. गुजरात :

गुजरात में भाजपा के नेतृत्व में सुशासन एवं जन-कल्याण की ख्याति विश्वभर में फैली हैं। समाज के हर वर्ग तक सुशासन द्वारा जन-हित सेवाएँ गारंटी करने में गुजरात में भाजपा सरकार निरंतर कार्यरत हैं। इस श्रृंखला में, स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2006 में आई 'चिरंजीवी योजना' उल्लेखनीय हैं। इस योजना के तहत माता मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण हेतु डाक्टर्स को वित्तीय अभिप्रेरण देते हुए BPL परिवारों को सरिकारी मदद मुहैया करायी जाती हैं। कन्या एवं महिला सशक्तिकरण हेतु भी गुजरात में भाजपा सरकार ने कई उल्लेखनीय कदम उठाये हैं, जिनमें बेटी बचाओ, सरस्वती साधना योजना, सखी मंडल योजना, आदि शामिल हैं।

बिजली उत्पादन एवं उद्यमिता, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी भाजपा शासित गुजरात सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं। वर्ष 2014 में गुजरात को सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में देश भर में पहला स्थान मिला है, फिर चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो या फिर राज्य द्वारा संचालित योजना।

6. महाराष्ट्र :

महाराष्ट्र में शिव-सेना के साथ गठबंधन में भाजपा सरकार ने सामाजिक उत्थान हेतु 'जुनका-भाकर' योजना 1995 में प्रारंभ हुई। पहले योजना में केवल ज्वार खाने वाले गरीब जनता को 2 रुपये में

एक किलो चावल की पेशकश थी, बाद में, भारतीय जनता पार्टी के अपील पर 1रूपए में 'जुनका भाकर' भोजन शामिल किया गया। सरकार ने स्टालों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जो की 180 वर्ग फुट से अधिक नहीं थे और प्रत्येक स्टाल दैनिक कम से कम 200 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया। वर्ष 2007 तक 6311 Zunka Bhakar केन्द्र संचालित थे। स्टाल मालिकों को जुनका भाकर के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री और विज्ञापन की जगह के द्वारा मुनाफा कमाने की इजाजत हैं। सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के अलावा, इस योजना में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से स्थानीय महिला मंडल, स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिलों में केन्द्रों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई।

7. गोवा :

गोवा में भाजपा सरकार ने शासन में आते ही घरेलू कल्याण हेतु अपनी कटिबद्धता दर्शाई। शासन में आते ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एवं गरीब समाज की घरेलू महिलाओं के परिवार कल्याण हेतु वर्ष 2012 में गृह आधार योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत सम्बंधित वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000रूपए दिए जाते हैं, जिससे उनका परिवार जीने का एक उचित स्तर को बनाए रख सके। इस योजना में 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी शादी-शुदा महिलाएं को लाभ दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आय 3लाख रूपए प्रति वर्ष से कम है, और गोवा के निवासी हैं। इस श्रेणी में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाऐं जिनकी सालाना आय डेढ़ लाख रूपए तक है, भी शामिल हैं। यह सुविधा सभी परिवारों को उनके बैंक अकाउंट में आधार लिंक के जरिये आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। हर वर्ष 15000 आवेदन स्वीकार होते हैं।

8. कर्नाटक :

कर्नाटक राज्य में भाजपा को बहुत कम समय शासन करने के अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु इस कम समय में भी, भाजपा के नेतृत्व में राज्य में सरकार ने दीर्घदर्शी नीतियाँ लाई। जिसमे सर्व प्रथम वर्ष 2008 में आई राज्य की स्किल-डेवलपमेंट नीति है। इस निति का मिशन कौशल विकास प्रणाली के तहत कौशल और ज्ञान के माध्यम से सभी को खासकर युवाओं को सशक्त बनाने का था। वर्ष 2008 में आई इस दीर्घदर्शी नीति का अनुसरण गत वर्षों में हुआ और कर्नाटक में आज

NSDC के गठन के बाद 'कौशाल्यासिरी सेवा' सुचारू रूप से संचालित हैं।

कम समय के शासन में भाजपा सरकार ने एक और दीर्घदर्शी योजना का शुभारम्भ राज्य में किया, 'निरंतर ज्योति योजना'। इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 2008 में गैर-कृषि के लिए 24 घंटे, 3 चरण बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए हुआ जिसमे घरेलू, वाणिज्यिक बिजली, पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण उद्योग, दूध डेयरियां आदि शामिल हैं। इस योजना पर क्रियान्वयन आज भी सुचारू रूप से कर्नाटक में जारी हैं।

इस उल्लेखनीय योजनाओं के अलावा, प्रदेश में भाजपा सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य कार्यक्रम (MADILU योजना, आदि), मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण प्रोग्राम (2007), जल निर्मला, आदि भी सराहनीय हैं। कर्नाटक ने कृषि के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया तथा 'शून्य' प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण सुनिश्चित किया। 2011-2020 को सिंचाई दशक घोषित किया गया।

9. मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य BIMARU के दर्जे से उभरने में सक्षम हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनों का सफल प्रारूप बनाकर उन्हें सफलता से लागू भी किया। सरकार की प्रख्यात 'लाडली लक्ष्मी योजना' का शुभारम्भ 2007 में हुआ, जिसका उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना है। जिस बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों तथा आयकर दाता न हों, और द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, तो उन्हें इस योजना लाभ मिलता हैं।

योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक 6-6 हजार रूपए मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा होते हैं अर्थात् कुल राशि 30000 रूपए बालिका के नाम से जमा होते हैं। बालिका के कक्षा-6 में प्रवेश लेने पर रू2000, कक्षा-9 में प्रवेश लेने पर रू4000, कक्षा-11 में प्रवेश लेने पर रू6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू6000

ई-पेमेंट के माध्यम से दिया जाता हैं। अंतिम भुगतान 1 लाख रूपए बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा-12 परीक्षा में सम्मिलित होने पर बालिका के विवाह पर जो कि 18 वर्ष की आयु के बाद होने पर भुगतान की जाती हैं। राज्य सरकार की योजना को देश भर में सराहना मिली हैं, एवं कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया हैं। इस सन्दर्भ में भाजपा सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सुशासन हेतु समाधान आनलाइन, पंचायत डायरेक्ट बातचीत, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 जैसी सफल प्रयास भी अमल में लाएं हैं।

10. छत्तीसगढ़ :

छत्तीसगढ़ में गरीबी, कुपोषण और भुखमरी से पीड़ित जनता को भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार ने काफी राहत दी। सर्व प्रथम, वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ फूड सिक्यूरिटी एक्ट पारित हुआ जिसके तहत राज्य के लोगों के लिए अच्छे पोषण के लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा कम कीमत पर, हर समय गरिमा से जीवन जीने के लिए उपलब्ध करने की जिम्मेदारी राज्य ने ली। अन्त्योदय, प्राथमिक, जनरल और अपवर्जित घरों को इस कानून के दायरे में लेकर, मासिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 35किलो चावल, गेहूं, दाल, और आयोडीन नमक कम कीमतों पर उपलब्ध कराया गया। इस अधिनियम से राज्य के 42 लाख परिवारों को फायदा हुआ। कृषि ऋण भी 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

राज्य सरकार की कुपोषण से लड़ने के लिए फुलवारी योजना भी सराहनीय हैं। प्रशासन ने आंगनवाड़ी के जरिये गांवो में सभी को भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराया। धनराशि पंचायत को हस्तांतरित किया जाता है, जो कि माताओं की एक समिति को सौंप दी जाती है। समिति गांव के भीतर खाद्य स्रोत या स्थानीय बाजारों में अनाज खरीदकर, फिर बारी बारी से माताएं पकाने का कार्य करके अपने बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मुहैया करते हैं। इस योजना से सरकार सिर्फ 50,000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी हर साल में खर्चकर, स्टाफ और निर्माण लागत से मुक्त है और 12 बच्चों और पांच माताओं एक उच्च गुणवत्ता वाला आहार मिल पाता है। यह सुशासन और जन-कल्याण का द्योतक है। ❍❍